

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण विकास विभाग**

मनरेगा के अंतर्गत होने वाले ग्रामीण कार्यों के गुणवत्ता की स्वतंत्र निगरानी हेतु विभाग कटिबद्ध है। इसके मद्देनजर राज्य स्तरीय गुणवत्ता अनुभवक (State Quality Monitor) की व्यवस्था की गई है। "State Quality Monitor" (SQM) की नियुक्ति के लिए पैलल तैयार करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के वेबसाइट rdd.bih.nic.in पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि दिनांक १९.०६.२०१९ को 5 PM तक होगी।

- i. SQM की प्रतिनियुक्ति विशेष कार्य आधारित होगी, जिसके लिए उन्हें जिलों का दौरा करना होगा। तत्पश्चात विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करना होगा। इसके लिए उन्हें मनरेगा अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की गुणात्मक जाँच करनी होगी तथा लाभान्वितों से मिल कर, उनके द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी लेनी होगी।
- ii. मनरेगा के अलावा SQM की प्रतिनियुक्ति, अन्य कार्यों के गुणात्मक समीक्षा में भी की जा सकती है। जिसे यथोक्त तर्ज पर ही करना होगा।
- iii. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त अन्य कार्यक्रम संबंधी शिकायतों की जाँच हेतु भी SQM की प्रतिनियुक्ति की जा सकती है।

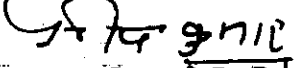
**नियुक्ति के शर्तें :-**

1. SQM का चयन, प्रशासन, शिक्षा, लेखा, अंकेक्षण, पुलिस, अभियंत्रण, कृषि, योजना एवं सांख्यिकी, पशुपालन एवं मत्सय सेवा के अवकाश प्राप्त अधिकारियों, जो संयुक्त सचिव अथवा इसके उपर स्तर के हो तथा समाज शास्त्र / सामाजिक क्षेत्र / के कार्यों का अनुभव हो, से किया जायेगा।
2. SQM का चयन दो वर्षों के लिए होगा। उनके द्वारा संपादित कार्यों की वार्षिक समीक्षा की जायेगी। तदोपरान्त कार्य सेवा का विस्तार एक वर्ष हेतु किया जा सकेगा। कार्यों से असंतुष्ट होने की स्थिति में नियुक्ति रद्द की जा सकती है।
3. मानदेय:- १५००/- रु०(पन्द्रह सौ रु० मात्र) प्रतिदिन (यात्रा भत्ता अलग से) एक जिले का दौरा SOP के तहत 5 दिनों / निर्दिष्ट दिनों के लिए होगा (यात्रा के अलावा)। प्रतिवेदन हेतु ३०००/- रु०(तीन हजार रु० मात्र) अलग से देय होगा।

**योग्यता :-**

अच्छे सत्यानिष्ठ एवं उत्कृष्ट ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो।

अवधि सीमा - ६६ वर्ष (दिनांक - ०१.०७.२०१९)।

  
सचिव २७५५५  
ग्रामीण विकास विभाग